(c) if so, the reasons therefor;

(d) the steps taken to increase the production of Shrimp with the increase in demand of Shrimp in the international market; and

(e) the details thereof;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The annual production of shrimp during 1995-96 to 1997-98 is given below:

Year	Shrimp Production (000 tonnes)
1995-96	331
1996-97	361 (Provisional)
1997-98	362 (Provisional)

(b) There has been no decline in the shrimp production during their above period.

(c) Does not arise.

(d) & (e) The steps taken by the Government for increasing the production of shrimp inter alia include:—

(i) development of scientific shrimp farming through Brackishwater Fish Farmers Development Agencies and providing package of technical, financial and extension support to shrimp growers.

(ii) encouraging establishment of integrated shrimp farms and support facilities such as seed hatcheries, feed mill, etc. in the Government/public/private sectors.

(iii) human resource development by establishing demonstration-cum-training centres; and

(iv) issue of guidelines outlining measures for development and management of sustainable brackishwater aquaculture practices, etc.

नैफेड में धन का दुरुपयोग

954. **श्री रामजी लाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में "नैफेड" में व्यापक स्तर पर सरकारी धन का दुरुपयोग जांच समिति की रिपोर्ट ने खुलासा किया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो सरकारी धन का दुरुपयोग किस प्रकार और किन मदों में किसके निर्देश पर किन कर्मचारियों के द्वारा किया गया;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) 06.01.1999 को "राष्ट्रीय सहारा" में नैफेड में धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) से (घ) इस विभाग द्वारा की गई जांच और इस मामले में प्राप्त कुछ अन्य शिकायतों के आधार पर, यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आगे भी जांच के लिए भेजा गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कथित अनियमितताओं के संबंध में नैफेड के कुछ प्राधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जैव उर्वरकों के माध्यम से दूसरी हरित क्रांति

955. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में जैव उर्वरकों के प्रयोग से दूसरी हरित क्रांति लाई जा सकती है;

(ख) क्या जैव-उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने के संबंध में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम किसानों के अनुकूल होंगे; और

(ङ) सरकार ने जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) परंपरागत रूप से रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल किए जाते रहे हैं तथा इनसे फसल उत्पादकता और मृदा की उर्वरता बढ़ने में मदद मिली है। फसल उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता बढ़ने से जैव ऊर्वरकों और कम्पोस्ट/खेत से प्राप्त खाद जैसे जैविक उर्वरकों के माध्यम से पोषक तत्वों के पूरक संसाधनों के उपयोग का महत्व बढ़ रहा है। इन उर्वरकों का एक विशेष लाभ यह है कि ये पर्यावरण के लिये अनुकूल हैं तथा मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिये, विशेष कर दूसरी हरित क्रान्ति लाने हेतु पोषक तत्वों का एक सस्ता स्रोत है।

(ग) और (घ) भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि में जैविक उर्वरकों तथा कम्पोस्ट/खेतों से प्राप्त खाद के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसान इन स्रोतों को फसल उत्पादन बढ़ाने और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में बहुत उपयोगी पाते हैं।

(ङ) उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान जैविक उर्वकों के विकास और उपयोग की योजना के अन्तर्गत कम्पोस्ट संयंत्र लगाने के लिये 3.90 करोड़ रुपये तथा जैविक ऊर्वरकं को बढ़ावा देने के लिये 12.63 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। नौंवी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान जैविक उर्वरकों के उत्पादन हेतु अनुदान पर 0.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पोषण के इन स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिये किसानों के खेतों पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

Production of Vegetables and Fruits

956. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of the production of vegetables and fruits during the last three years and the details of exports during that period;

(b) whether it is a fact that India grows a wide range of fruits and vegetables yet we are not even a blip on the world horticultural exprot map and if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps Government propose to take to augment the export of horticultural products?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The estimated production figures of fruits and vegetables are available upto 1995-96 and export figures are available upto 1996-97. The estimatted production and their export during the last three years are given as under:—

(million tonnes)

Year	Production
1993-94	103.03
1994-95	105.88
1995-96	113.09

Year	Export
1994-95	0.55
1995-96	0.54
1996-97	0Ä70

(b) Yes, Sir. The main reasons for India's dismal performance are:

— lower per capita availability of fruits and vegetables in the country.
— lack of proper pre and post-harvest practices.
— lack of cold chain linkage and other infrastructural facilities.
— lack of good packaging.

(c) Government of India through Agricultural and Processed Food Products Exprot Development Authority (APEDA) has proposed to augment the export of horticultural products by implementing following schemes/ programmes:

1. Integrated Programmes for Pre and Post Harvest Management.
2. Preparation of Manuals.
3. Promotion of Pack House Concept.
4. Vapour Heat Treatment Experiment.
5. Controlled Atmosphere/Modified Atmosphere Experiments Transportation.
6. infrastructure facilites.